the number of problem villages has increased. I would like to know from the hon. Minister whether he will grant more money for the drought prone States, specially West Bengal.

MR. SPEAKER: This is a Plan allocation which has been done, not an adhoc allotment.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Will he increase the money for drinking water in the drought prone areas?

MR. SPEAKER: I do not think, this question concerns you.

SHRI BUTA SINGH: It is done through Plan allocation, and the Central Government gives assistance, but the major portion comes from the State Government under the NMP Programme. We have definitely given a special thought and under the 20-Point Programme, we have highlighted this problem to the State Governments. Our grant is on a matching basis. If the State Governments come forward with further proposals, and plans of very very difficult areas, we are always prepared to consider it.

DR. KRUPASINDHU BHOI: Is the hon. Minister aware of the fact that there is lack of infrastructural facilities and lack of technical expertise for supply of protected drinking water to all the villages of the country? Is there any course in the engineering departments of colleges for Ph. D., which looks after the protected drinking water supply in the country? I doubt, because in engineering courses, there is no such course; it is only a diploma course. We have spent more than Rs. 150 crores on these schemes, but there is lack of technical expertise and infrastructural facilities. Will the hon. Minister look into this matter, and ask the different engineering colleges of the country to introduce a course regarding primary basic knowledge of this particular branch, that is, to supply protected drinking water throughout the country.

SHRI BUTA SINGH: This is a suggestion for action.

Survey of Ground Water Potential in Bihar

105. SHRI RAMS WARUP RAM Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a survey has been made to explore the ground water potential in Bihar, especially in Nowgang, Gaya, Nawada and Aurangabad districts; and

(b) if so, with what results?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) (a) Yes, Sir. For exploration of ground water potential in Bihar, hydrogeological surveys have been carried out by the Central Ground Water Board *inter-alia* in the districts of Gaya, Newada and Aurangabad. There is however, no Nowgang district in Bihar.

(b) Based on the ground water surveys carried out by the Central Ground Water Board, the ground water potential available for further development is as under:

Gaya: 357 million cubic meters

Nawada: 380 million cubic meters, and

Aurangabad: 665 million cubic meters

MR. SPEAKER: You start teaching georpraphy also in the Parliament House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): Geography is part of politics, Sir.

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने के पहले मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि आप मार्च, 1981 में गया कृषक सम्मेलन में गये थे तथा आप ने वहां की ज़मीन स्वयं देखी थी। आप ने उस समय खेद प्रकट करते हुए कहा

था कि यहां की ज़मीन इतनी उपजाऊ होते हुए भी सिंचाई का अभाव है ....

अध्यक्ष महोदय : मैं तो अब भी कहता हूं ।

श्री रामस्वरूप राम : बिहार का, खास तौर से दक्षिण-बिहार का एरिया सुखाड़-प्रोन-एरिया है । आप देखगे कि वहां नवादा, पालामऊ, गया, औरंगाबाद, ये सब हर वर्ष सुखाड़ की चपेट में आते हैं । कुछ स्कीमें वहां पर बनी हैं, खास कर नहरें वगैरह बनी हैं, लेकिन वे सभी योजनायें बरसाती नदियों पर आधारित हैं । कोई भी प्रश्न पूछने से पहले वहां का थोड़ा भौगालिक ज्ञान हाउस के सामने रखना बहुत आवश्यक है ...

अध्यक्ष महोदय : आप तो शुरुआत ही गलत कर बैठे ।

श्री रामस्वरूप राम : वहां पर जितनी नदियां हैं सब बरसाती नदियां हैं, पानी गिरता है तो सिंचाई होती है, अन्यथा सुखाड़ की चपेट में आ जाता है । वहां पर अण्डर-ग्राउण्ड-वाटर-रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है, यदि उस का समुचित प्रयोग किया जा सके तो वहां के लोगों को परमानेण्ट इरिगेशन मिल सकती है । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध होते हुए भी ....

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये ।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, आप किसानों का हित चाहने वाले हैं ; उन की बात को सुनते हैं, इस लिए मुझे थोड़ा कहने दीजिए— मैं वहां की स्थिति बतलाना चाहता हूं । वहां पर गया, नवादा और औरंगाबाद पहले तीनों एक ही ज़िले थे, नवादा में 101 ट्यूबवेल लगे हैं, गया में 180 ट्यूबवेल हैं और औरंगाबाद में, मैं समझता हूं, 80–90 ट्यूबवेल हैं । ज्योलाजिकल सर्वे के अधिकारी वहां जाते हैं और कहते हैं कि यह राकी एरिया है, यहां अण्डर-ग्राउण्ड-वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । जब कि उस के बगल में छोटा किसान ट्यब-वेल लगा कर पटवन कर रहा है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुरुआ, बोधगया, फतहपुर, वजीरगंज, अत्री, नबीनगर, सिरदला, राजोली, कुटुम्बा क्षेत्रों को राकी एरिया बता कर नेग्लैक्ट किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको रोकना पड़ेगा, रामस्वरूप राम जी । आप के आगे भी राम है, पीछे भी राम है ।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं ....

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछगे या नहीं ?

श्री राम स्वरूप राम : सवाल ही पूछ रहा हूं । यह किसानों का सवाल है, **अध्यक्ष महोदय** :

अध्यक्ष महोदय : किसानों का सवाल है तो दूसरे ढंग से कीजिए ।

श्री रामस्वरूप राम : इतना मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उस की बात को सुन कर गम्भीरता से लेते हैं, अन्यथा मैं सवाल पूछ कर ही बठ जाता ।

SHRI SUNIL MAITRA Sir, he is utilising the time.

MR. SPEAKER: No, he is not utilising. He is Misutilising.

श्री रामस्वरूप राम : मैं जानना चाहता हूं—अभी तक ग्राउण्ड वाटर रिसोर्सेज़ का कितने प्रतिशत इस्तेमाल हुआ है तथा बाकी रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करने के लिए क्या सरकार उस एरिये के लिए कोई बृहद योजना बनायेगी, जिस के द्वारा वर्तमान पंच वर्षीय योजना में भी कुछ कम्प्लीशन कर सकेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा : प्रश्न यह था कि गया, नवादा और औरंगाबाद जिलों में पानी का सर्वेक्षण किया गया है तथा उस के नतीजे क्या रहे? इस विषय में मैंने कुछ आंकड़े बतलाये हैं। यह सही है कि इन ज़िलों में अण्डर-ग्राउण्ड-वाटर काफ़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन जहां तक सर्वे का प्रश्न है—इन तीनों ज़िलों का, करीब-करीब सब का सर्वे पूरा हो चुका है। गया में हम ने सारे जिले का सर्वेक्षण कराया है और वह हो चुका है। इसी तरह से नवादा और औरंगाबाद का भी हो चुका है। अब प्रश्न यह आता है कि वहां पर पानी की उपलब्धि को देखते हुए योजना क्या बनाई जाए। उस के लिए राज्य सरकार सक्षम है और जितने कुंए बनते हैं, उन में किस प्रकार से मदद दी जाए, इससे भी राज्य सरकार परिचित है। जो माइनर इर्रीगेशन की योजना बनती है, उस के लिए बैंक और दूसरी इंस्टीट्यूशन्स भी मदद देती हैं। तो जो भी योजना राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए और वहां पर कुओं के लिए हमारे पास भेजेगी, उस पर हम पूर्ण रुप से विचार करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

श्री रामस्वरूप राम : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। जियोलाजीकल सर्वे आफ़ इण्डिया ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस में इस क्षेत्र को रोकी एरिया डिक्लेयर किया है जैसे गुरुआ का एरिया है, बौधगया, रजोली, अतरी और कुटुम्बा का एरिया है। इन सब एरियाज की उन्होंने रोकी एरिया कहा है और यह कहा है कि यहां पर पानी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं और आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अण्डर-ग्राऊण्ड वाटर रिसोर्सेज़ इन तीन जिलों में हैं। तो मैं आप से एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जियालार्जीकल सर्वे आफ़ इण्डिया ने जो इस को रोकी एरिया डिक्लेयर किया है, तो कोई ऐसी मशीनें इन तीनों जिलों में भेजी, जिससे इन एरियाज के लोगों को पानी मिल सके।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, यह जो रोकी एरिया माननीय सदस्य बताते हैं, पहली बात तो यह है कि इस में बहुत थोड़ा एरिया ही रोकी एरिया है और वहां पर ड्रिलिंग कर के यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कितना पानी है, कितने नीचे पानी है और कितना पानी उपलब्ध हो सकता है। हमारे पास इस तरह के रिग्ज मौजूद हैं, जो पत्थरों को तोड़ कर इस का सर्वे कर सकें। मैं फिर निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इन एरियाज के लिए अगर कोई योजना बनाती है, तो जो भी मदद हम कर सकते हैं, वह करेंगे वैसे राज्य सरकार इस को कर सकती है और यह उसकी क्षमता में है।

श्री रामस्वरूप राम : आप राज्य सरकार को कम से कम निर्देश तो दे सकते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : आप भी राज्य सरकार से बात करें और हम भी इस सम्बन्ध में बात करेंगे और जो दिक्कत राज्य सरकार को शोध कार्य में या इस

क्षेत्र के विकास में होगा, केन्द्र सरकार इस में उस की पूरी मदद करेगी ।

श्री कुंवर राम : मंत्री जी ने अभी बताया है कि अण्डरग्राऊण्ड वाटर पोटेंशियल के बारे में सर्वे कराया है । मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सर्वे कब कराया है ? जहां तक मुझे पता है, इधर निकट भविष्य में यह नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप ने यह सर्वे कब करवाया है ।

दूसरी बात यह है कि हम ने गत वर्ष सितम्बर में एक पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा था जब हम नवादा क्षेत्र का भ्रमण कर के लौटे थे । बिहार के नवादा जिले में कुछ ग्राम जो हैं, जो वह डिस्ट्रिक्ट हैं, वह ड्राऊट-प्रोन है । अभी हमारे माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह ने जो पेय जल के सम्बन्ध में उत्तर दिया है, उसी के क्रम में हम यह जानकारी भी लेना चाहते हैं कि वह जो ड्राऊट-प्रोन एरिया है, वहां पर विशेष तौर पर पानी के स्रोतों को उपलब्ध करने के लिए और खासकर पेय जल के लिए कौन से उपाय आप ने किये हैं । वह आलरेडी एक ड्राऊट-प्रोन एरिया है । मैं एक निश्चित प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि बहुत पुराने वक्त में इस का सर्वे कराया गया था और सर्वे कराने का जो नतीजा निकला था, उसमें इस को रोकी एरिया बराबर कहा गया है ? साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जब प्राइवेट ट्यूबवेल्स वहां पर खोदे गये, तो वहां रोक्स का प्रश्न नहीं उठा और जो प्राइवट ट्यूबवेल लगाए गये, उस में काफ़ी पानी मिला । फ़र्क इतना ही था कि वह स्मालर डाइमेंशन का था लेकिन गवर्नमेंट की एजेन्सी ने इस पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए अधूरा काम कर के छोड़ दिया जब कि प्राइवेट ट्यूबवेल वालों को पानी मिला । अगर किसान के लिए वह बड़े डाइमेंशन का हो सकता तो उसको काफ़ी पानी मिल सकता था । सरकार के यह न करने का क्या कारण है ? क्या इस पर कोई ध्यान दिया गया ? क्या सर्वे रिपोर्ट में इसकी कोई जानकारी है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने निवेदन किया है जहां तक सर्वे का प्रश्न है सर्वे करने के बाद उन क्षेत्रों में बोरिंग किया गया । मेरे पास इसके आंकड़े हैं कि कितने बोर के कुएं खोदे गये ....
(व्यवधान)

सन् 1972 से यह सर्वे का काम चल रहा है । सब राज्यों में चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है । आपके यहां तीन जिलों का पूरा सर्वे हो गया था । उन का डिटेल्ड सर्वे कर के, बोर कर के पता लगाया जा रहा है । हमें यह भी पता लगा है कि एक तरह से नवादा में 4 मीटर से 14 मीटर पर पानी मिल रहा है और गया में 1.5 मीटर से 10 मीटर पर पानी मिलता है ।

श्री कुंवर राम : हम वहां के संसद् सदस्य हैं । हम बराबर जानते हैं और बराबर देखते हैं । अगर सरकार को यह सूचना दी गई है तो यह सरासर गलत सूचना है ।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग पता करवा लीजिए और इनको भी वैरीफाई करवा दीजिए । यह अच्छा रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य सर्वे कराने का है । उस सर्वे

के पश्चात् कितने कुएं खोदे जाएं, किस इलाके में खोदे जाएं, कितने बोर के खुदते हैं, या अधूरे रह जाते हैं, या नहीं रह जाते हैं, यह सब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जहां तक सर्वे का प्रश्न है, उसकी जानकारी हम माननीय सदस्य को करा सकते हैं। अगर वे चाहेंगे कि आगे के लिए राज्य सरकार का कोई डिटेल्ड जानकारी कराई जाए तो वह करा सकते हैं जिससे कि इन क्षेत्रों का विकास किया जा सके।

SHRI SUNIL MAITRA: The hon. Member has levelled certain charges regarding the survey itself. The Minister has not replied to the charges.

MR. SPEAKER: Yes, Mr. Amal Datta.

SHRI AMAL DATTA: I have had the occasion to sit down with the officials of the Central Ground Water Board. My constituency happens to be a very difficult one, where saline water is there in the upper layers and one has to go below to a minimum of 600 ft. to get even drinking water. In the course of my discussion, I found that the survey was made in a casual manner, so that the survey report cannot be accurate; the reason being that the resources available to the Central Ground-water Board are not sufficient and they cannot do the necessary intensive survey till all the areas to which they are to cater are covered, to come to a proper finding. This has not been done, so far as my constituency is concerned. I am certain about it and I think the proper survey has not probably been done anywhere in the country with the meagre resources at their disposal.

Secondly, the rigs about which the Minister has spoken, for being rocks the drill costs about Rs. 25 lakhs. And in my area where one has to go 600 ft. or below, from the ground level, it costs about Rs. 45 lakhs. The State Government do not have that kind of budget. The money which is doled out by the Central Government to the State Government is not enough. I want to know whether the Minister Will take a note of this and see that the Central Ground Water Board conducts adequate investigation, not this kind of casual investigation. And Secondly here the water availability is so difficult, will he see that the State Government's resources are supplemented, and that particularly, money is given for the purpose of buying the boring drills?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: The hon. Member has correctly stated that the survey we had done is not adequate because of the rigs. Well, the Central Ground Water organisation has got only 59 rigs which I rightly concede are not enough, we are formulating a very big programme and submitting it to the proper authorities to augment the number of rigs and strengthening the organisation. We propose to have a separate division to cover West Bengal and Bihar this year because of the potential there and when this organisation is in a strong position, some of the shortcomings which the hon. Member has mentioned will, to some extent, vanish.

As regards strengthening the State Governments' organisations with deep drill and all that, they have a way of procuring rigs through their own plan alocations. If they want any assistance from the Central Government of a technical nature, we will be prepared to help them.

Famine Situation in Bihar and Adjoining States.

†106. SHRI BHOGINDRA JHA: Will the Miniser of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether most parts of Bihar and adjoining States are facing famine situation due to abnormally severe drought resulting in failure of Bhadai, Kharif and Rabi crops;